आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 01.05.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार, उत्तराखंड को 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटित करेगी।
- राज्य में निर्माण कार्यों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को रेरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
- प्रदेश में आपदा चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए कल सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का परीक्षण अलर्ट जारी होगा, प्रशासन की लोगों से इसे केवल परीक्षण मानकर घबराने से बचने की अपील।
- हरिद्वार में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय का दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित; जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और समग्र विकास पर हुई चर्चा।

बिजली आवंटन

केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने राज्य को 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का निर्णय लिया है।
यह बिजली पश्चिमी क्षेत्र के अनआवंटित पूल से उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था आज से 30 जून तक लागू रहेगी।
इस फैसले से राज्य में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

निर्णय

राज्य में निर्माण कार्यों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण– रेरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरी व्यवस्था ऑनलाइन और समयबद्ध हो सकेगी।
सचिवालय में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत नियोजित क्षेत्रों के बाहर की परियोजनाओं के मानचित्र भी पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे और संबंधित प्राधिकरणों को इससे जोड़ा जाएगा।
बैठक में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बढ़े हुए शुल्क से लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर सभी विकास प्राधिकरणों से एक सप्ताह के भीतर संशोधित प्रस्ताव मांगे गए हैं।
एक अन्य निर्णय के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अब पंचायतों को नक्शा पास करने का अधिकार नहीं रहेगा। यह जिम्मेदारी केवल विकास प्राधिकरणों के पास होगी।
अवैध निर्माण और अनियमित कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए रेरा और प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
आवास सचिव ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और लोगों को अनावश्यक दिक्कतों से राहत मिलेगी।

सारा बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए स्प्रिंग एंड रिवर रिज्युविनेशन अथॉरिटी–सारा, के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सारा को एक वर्ष की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने और सभी कार्यों की प्राथमिकता व समयसीमा तय करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि सभी नदियों पर एक साथ काम करने के बजाय चिन्हित नदियों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू किया जाए।

मुख्य सचिव ने चेकडैम की श्रृंखला बनाने और उनके रखरखाव तथा डिसिल्टिंग को योजना में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने भूमिगत जल के रिचार्ज से जुड़े कार्यों को 30 जून तक पूरा करने और नैनीताल व देहरादून में भूमिगत जल संवर्धन कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
श्री बर्धन ने कहा कि सभी कार्यों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए और ज़िला स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

वरिष्ठ नागरिक सम्मान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में वृद्धाश्रमों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर काम किया जा रहा है और कई स्थानों पर नए भवन निर्माणाधीन हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, सहायक उपकरण और निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हल्द्वानी में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह में भाग लेते हुए श्री धामी ने बुजुर्गों को समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों का सम्मान किसी भी सभ्य समाज की पहचान है और उनके अनुभव समाज को दिशा देते हैं।

जर्जर विद्यालय भवन ध्वस्तीकरण

देहरादून में जर्जर विद्यालय भवनों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 64 में से 56 भवनों को ध्वस्त कर दिया है, जबकि शेष भवनों पर कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई तेज़ी से की गई है। प्रशासन के अनुसार, इन भवनों की जर्जर स्थिति बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई थी।
मुख्य शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, ध्वस्त किए गए भवनों में माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा कई निष्प्रयोज्य कक्षा कक्षों को भी हटाया गया है और बाकी कक्षों को एक माह के भीतर ध्वस्त किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
जिलाधिकारी ने शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि जर्जर भवनों की पहचान और कार्रवाई में कोई लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शेष भवनों को भी जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम/परीक्षण अलर्ट

उत्तराखंड में आपदा से जुड़ी चेतावनियों को आम लोगों तक तेजी से पहुंचाने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के तहत कल परीक्षण अलर्ट जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में सूचना प्रणाली की कार्यक्षमता को परखना और लोगों तक समय पर संदेश पहुंचाना सुनिश्चित करना है।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह पहल आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के तहत की जा रही है, ताकि मौसम और आपदा संबंधी सूचनाएं प्रभावी ढंग से आमजन तक पहुंच सकें।
यह परीक्षण विभिन्न मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जाएगा, जिससे संदेशों के प्रसार और उसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।
प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि इस संदेश को केवल परीक्षण अलर्ट के रूप में ही लें और घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कहा गया है कि भविष्य में वास्तविक आपदा की स्थिति में जारी अलर्ट को गंभीरता से लिया जाए और प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए।

चिंतन शिविर

हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय का दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और समग्र विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्रालय के अधिकारियों ने समावेशी विकास, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और जनजातीय समुदायों की भूमिका पर विचार रखे।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखते हुए उनके विकास पर जोर दिया जाएगा।

शिविर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति संरक्षण और डिजिटल सशक्तीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के अधिकारी और विशेषज्ञ भी शामिल हुए।

बदलाव

प्रदेश सरकार ने मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब कक्षा एक से आठ तक संचालित मदरसों की मान्यता जिला स्तर से दी जाएगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के मदरसों के लिए राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बंद पड़े मदरसों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने वन क्षेत्रों में मानव–हाथी संघर्ष कम करने के लिए मधुमक्खी पालन नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने और वन्यजीवों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक अवरोध बनाने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्णय लिया गया। इसके तहत एक करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी, पांच करोड़ रुपये तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त और उससे अधिक लागत के कार्य शासन स्तर से स्वीकृत किए जाएंगे।

इसके अलावा वन विभाग में भर्ती नियमावली में संशोधन, ठेकेदारों की कार्य सीमा बढ़ाने, विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियमावली को मंजूरी और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाने जैसे निर्णय भी लिए गए।

मौसम

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश व ओलावृष्टि से विभिन्न स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ।

मसूरी में दोपहर बाद तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे गर्मी से राहत मिली। ओलावृष्टि के कारण सड़कों और छतों पर बर्फ जैसी परत जम गई। वहीं पर्यटक, माल रोड और गन हिल जैसे स्थानों पर इस मौसम का आनंद लेते नजर आए।

हरिद्वार में भी मौसम ने अचानक बदलाव दिखाया। तेज हवाओं और काले बादलों के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली।

इधर, राजधानी देहरादून के गुच्चूपानी में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से सात पर्यटक बीच धारा में फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

उधर केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर रुक–रुक कर बारिश जारी रही। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। खराब मौसम के बावजूद यात्रा जारी है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखी गई हैं।

निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी जरूरी कार्य प्राथमिकता के आधार पर समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में चारधाम यात्रा मार्गों की मानसून से पहले दुरुस्तीकरण को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून आने से पूर्व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जरूरी उपचार कार्य पूरा कर लिया जाए।

बैठक में लोक निर्माण विभाग, बीआरओ, एन.एच.ए.आई और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी शामिल हुए।